राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9634/2018

पुष्पा पाटीदार पुत्री श्री कंवर लाल पाटीदार, आयु लगभग 30 वर्ष, पत्नी श्री राकेश, ग्राम दलोट तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़
4. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ (राज.)
5. तहसीलदार, तहसील और जिला प्रतापगढ़ (राज.)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री राहुल भाटी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री दीपक चांडक, एजीसी।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

03/05/2024

1. याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें याचिकाकर्ता को दिनांक 08.06.2018 की चयन सूची के अनुसार टीएसपी क्षेत्र के लिए अनारक्षित श्रेणी (महिला) में उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध दिनांक

12.04.2018 (अनुलग्नक 7) के विज्ञापन के अनुसार शिक्षक स्तर- I के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है, जिसमें उसके समकक्षों की नियुक्ति की तारीख से सभी परिणामी लाभ शामिल हैं।

2. संक्षेप में, तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने टीएसपी क्षेत्र के लिए शिक्षक स्तर-1 के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता, एक महिला श्रेणी की उम्मीदवार का चयन दिनांक 08.06.2018 की चयन सूची के अनुसार किया गया था। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 ने वर्ष 2014 में जारी उसके टीएसपी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया और इसके बजाय उसे वर्ष 2018 में जारी एक नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता को यह आधार पर देने से मना कर दिया गया कि उसने टीएसपी क्षेत्र के बाहर विवाह किया था। इसलिए यह याचिका दायर की गई।

3. तदनुसार, प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाब में निम्नलिखित विशिष्ट प्रारंभिक आपत्तियां ली गई हैं:-

> “1. मामले में बाद की घटनाएं हुई हैं और याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पहले ही 15.04.2019 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका के माध्यम से 15.04.2019 के आदेश पर हमला नहीं किया है जिसके साथ याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पहले ही खारिज कर दी गई है। इस प्रकार, बाद के भौतिक विकास के कारण, तत्काल रिट याचिका खारिज होने योग्य है। 15.04.2019 के आदेश की एक प्रति इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और अनुलग्नक-आर -1 के रूप में चिह्नित की जाती है।
>
> II. जिला स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन किया गया था और निम्नलिखित कारणों से, याचिकाकर्ता को योग्य नहीं पाया गया:
>
> > i. याचिकाकर्ता के पास 19.07.2013 की अधिसूचना के अनुसार तैयार किया गया एक विशेष बोनाफाइड प्रमाण पत्र था, जिस पर क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली बाद की अधिसूचना जारी करने के बाद विचार नहीं किया जा सकता था। विज्ञापन में दिनांक 04.07.2016 की अधिसूचना के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और उसी के अनुसार एक विशेष बोनाफाइड प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

ii. याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन दिनांक 18.06.2018 के माध्यम से तहसील कार्यालय, अरनोद में अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसार विशेष बोनाफाइड प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन कार्यालय में आज तक इसे दायर नहीं किया गया है।

iii. आवेदक, अपने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2018 के अनुसार, टीएसपी क्षेत्र की निवासी थी, लेकिन 18.01.2016 को गाँव कन्नलाखेड़ा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में शादी हुई थी, जो एक गैर-टीएसपी क्षेत्र है।

iv.आवेदक पत्राचार माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रहा था।

III. याचिकाकर्ता ने दो-तरफा प्रार्थना की है। पहली प्रार्थना के माध्यम से उसने प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देने के लिए कहा है कि वह याचिकाकर्ता को शिक्षक ग्रेड-III लेवल-I पर नियुक्ति दे। हालांकि, दूसरी प्रार्थना के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 को बिना किसी और देरी के तुरंत कानून के प्रावधानों के अनुसार विशेष वास्तविक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। पहली प्रार्थना सेवा रिट के दायरे में आती है जबकि दूसरी प्रार्थना स्पष्ट रूप से विविध रिट के दायरे में आती है जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से वर्गीकृत किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने मिश्रित प्रार्थना की है। जैसा भी हो, प्रार्थना खंड (बी) के माध्यम से की गई प्रार्थना मुख्य प्रार्थना लगती है और प्रार्थना खंड (ए) के माध्यम से की गई प्रार्थना परिणामी राहत लगती है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता खुद वस्तुतः स्वीकार करती है कि उसे क्षेत्र धारण करने वाली अधिसूचना के तहत वैध विशेष वास्तविक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुपस्थिति में नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी। इस प्रकार, इस आधार पर रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।"

4. उपरोक्त आपत्तियां निर्विवाद रहीं क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से हलफनामे पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। दूसरी ओर, यह पता चला कि याचिकाकर्ता के टीएसपी प्रमाण पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह विज्ञापन में निहित शर्त संख्या 11.2 के अनुसार वास्तविक नहीं लगता।

5. उपरोक्त शर्त सभी उम्मीदवारों पर लागू की गई है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता अपनी अस्वीकृति के खिलाफ न्यायालय में है, उक्त शर्त को याचिकाकर्ता के एकमात्र लाभ के लिए शिथिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि वह अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों पर बढ़त हासिल कर लेगी, जिनके प्रमाण पत्र भी उसी खंड को लागू करते हुए खारिज कर दिए गए थे।

6. इसके अलावा, उक्त खंड इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन भी नहीं है।

7. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

8. खारिज।

9. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।